राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 28 अप्रैल 2026
वर्ष 14, अंक 19, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

यूपी बनेगा ग्लोबल फार्मा हब, सीएम योगी...03

आईसीयू के लिए एक समान मानक होः सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर..12

गुरुग्राम में तोड़फोड़ से जुड़ी याचिका पर विचार करने से SC का इनकार

» आरडब्ल्यूए का कहना है कि इससे प्रभावित सेक्टरों में 3 दशकों से अधिक समय से रह रहे करीब 1,500 परिवारों को अब अपनी संपत्तियों के तत्काल ढहाए जाने का खतरा मंडरा रहा है. आरोप है कि अधिकारी बिना किसी को अलग से 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए या सुनवाई का मौका दिए ही कार्रवाई कर रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को गुरुग्राम में चल रही तोड़फोड़ से जुड़े अभियान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, और याचिकाकर्ताओं से इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ले जाने का निर्देश दिया. साथ ही याचिकाकर्ताओं को आज ही हाईकोर्ट के सामने इस मामले का तुरंत ज़िक्र करने की भी आजादी दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे इस मामले पर दोपहर 1 बजे या लंच ब्रेक के तुरंत बाद सुनवाई करें।

सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने मौखिक रूप से इस केस का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में तोड़फोड़ का काम चल रहा है, और दावा किया कि यह कार्रवाई बिना किसी अनिवार्य कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर ही की जा रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ को लेकर कुछ नहीं कहा. आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है।

'आदेश की गलत व्याख्या कर शुरू हुई तोड़फोड़'

इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, 'लेकिन ये तो अनाधिकृत निर्माण हैं. अगर हाई कोर्ट अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है, तो एक शीर्ष संस्था के तौर पर हम इसमें बाधा क्यों डालें?' शंकरनारायणन ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि अधिकारियों ने हाईकोर्ट से पारित एक अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या करके तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये निर्माण कानूनी हैं. सीजेआई कांत ने इस पर कहा कि यह तर्क हाईकोर्ट के सामने ही उठाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका गुरुग्राम के सेक्टर-31 (लेन 635 से 937) के निवासियों की ओर से दायर की गई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई. इस आदेश ने 'स्टिल्ट + 4' (S+4) निर्माण नीति पर पूरे राज्य में रोक लगा दी है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिकारियों ने इस आदेश का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का अभियान शुरू कर दिया है, जिससे गुरुग्राम में हजारों निवासी प्रभावित हो रहे हैं।

2 अप्रैल के फैसले के खिलाफ स्ट में याचिका

यह स्पेशल लीव पीटिशन हाईकोर्ट के 2 अप्रैल के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो एक लंबित जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस रोक को एक 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि वे वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकें और बिना किसी लीगल नोटिस या न्यायिक फैसले के पूरे शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू कर सके। याचिका के अनुसार, S+4 निर्माण नीति पर हाईकोर्ट की रोक के बाद, राज्य के अधिकारियों ने 16 अप्रैल, को एक निर्देश जारी किया. उन्होंने इस आदेश की व्याख्या इस तरह की कि यह कई आवासीय सेक्टरों में चारदीवारी, रैंप और हरे-भरे इलाकों को तुरंत तोड़ने का अधिकार देता है. उनका तर्क है कि हाईकोर्ट ने केवल नीति संबंधी अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगाई थी, और उसने किसी भी तरह की तोड़फोड़ या अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया था।

RWA की ओर से कहना है कि इससे प्रभावित सेक्टरों में 3 दशकों से अधिक समय से रह रहे करीब 1,500 परिवारों को अब अपनी संपत्तियों के तत्काल ढहाए जाने का खतरा मंडरा रहा है. आरोप है कि अधिकारी बिना किसी को अलग से 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए या सुनवाई का मौका दिए ही कार्रवाई कर रहे हैं।

बाद में कहीं रोना न पड़े... बंगाल चुनाव में आईपीएस अजय पाल शर्मा पर बवाल

● टीएमसीने लगाए धमकाने के आरोप

● पश्चिम बंगाल चुनाव में पुलिस ऑब्ज़र्वर आई पी एस अजय पाल शर्मा विवादों में घिर गए हैं

उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल चुनाव में डायमंड हार्बर पुलिस जिले में पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा अपने बयान और भूमिका की वजह से विवादों में घिर गये हैं. उन पर उम्मीदवार और उनके परिवार पर धकमाने का आरोप लगा है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने फलता से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के सामने खड़े होकर चेतावनी दी. इस संबंध में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि टीवी9 हिंदी उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. अजय पाल शर्मा का वीडियो सोमवार दोपहर को सामने आया. वह फलता में तृणमूल उम्मीदवार के घर के सामने खड़े होकर अपने आस-पास के लोगों को 'धमका' रहे हैं. उनके साथ सेंट्रल आर्मी के जवान भी थे।

आईपीएस अजय पाल के बयान पर बवाल

वहां वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, अपने आस-पास के लोग, अच्छी तरह समझ लें अगर कोई कोई शरारत करेगा, तो उसे सही सजा मिलेगी. अगर कहीं से कोई खबर आती है कि कोई हंगामा करने या किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे. उन्होंने कहा, 'उनके परिवार वालों से कहो कि वह जो कर रहे हैं, उसके लिए बाद में रोएं नहीं. ' दूसर ओर, जहांगीर ने कहा कि वह किसी से नहीं डरते. जहांगीर ने कहा, 'मैं 5,000 लोगों के साथ एक पब्लिक मीटिंग कर रहा हूं. मैं किसी से नहीं डरता. मैं कोई लड़का नहीं हूं जिससे डरना पड़े. वे डायलॉग बोल रहे हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. यह काम नहीं करेगा।

टीएमसी ने आईपीएस पर साधा निशाना

अजय पाल शर्मा को लेकर टीएमसी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया. टीएमसी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के बदनाम सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अजय पाल को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना के लिए पुलिस ऑब्ज़र्वर नियुक्त किया है. यह वही ऑफिसर है जो अपने ट्रिगर-हैप्पी ठोक दो रवैये के लिए बदनाम है. उनका ट्रैक रिकॉर्ड और भी बुरा है।

टीएमसी ने लिखा, जनवरी 2020 में, अजय पाल को रामपुर से, जहां वह एस पी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था, जब एक रिपोर्ट में उनका और पाँच दूसरे आई पी एस ऑफिसर्स का नाम कैश-फॉर-पोस्टिंग स्कैंडल में आया था. भाजपा सरकार को एक एस आई टी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की।

टीएमसी ने लिखा, उन पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सबूत गायब करने और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के लिए भी केस दर्ज किया गया था. एफ आईआर एक 30 साल की महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि अजय पाल ने उससे शादी की, दूसरी महिलाओं के साथ अपने संबंध छिपाए, और बाद में जब वह अपनी शिकायतें लेकर डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के पास गई तो उसे फंसाया. चुनाव आयोग बंगाल के लिए इस तरह के इम्पर्शियल पुलिस ऑब्जर्वर को चुन रहा है. जाहिर है, भ्रष्ट और क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड अब इस नौकरी के लिए मुख्य क्वालिफिकेशन बन गया है।

संक्षिप्त ख़बरें

मार्ग दुर्घटना में भट्ठा मालिक की हुई मौत

भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर चौराहे के समीप हुआ हादसा

सिद्धार्थनगर। जिले के डुमरियागंज चन्द्रीपघाट मार्ग पर भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर चौराहे के समीप क्षेत्र के बायताल स्थित राजा भट्ठा मालिक की मार्ग दुर्घटना में मौत का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार भट्ठा मालिक राजाराम मिश्रा पुत्र स्वर्गीय हरिराम मिश्रा उम्र 55 वर्ष निवासी जोगिया थाना सोनहा जनपद बस्ती जो की भड़रिया की तरफ अपने बाईक से जा रहे थे तभी उक्त स्थान पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गये। घटना देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई,लोगों द्वारा उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंवा ले जाया गया जहां उनकी हालत गम्भीर देख डॉक्टरों ने उन्हें बस्ती के लिए रेफर कर दिया। बस्ती ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष भवानीगंज बृजेश सिंह ने बताया की उक्त घटना की हमें जानकारी नहीं है।

दिल्ली में गोल्ड जीतने के बाद अब बैंकॉक के लिए मिला भारत का प्रतिनिधित्व करेगा

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक स्वतंत्र प्रभात www.swatantraprabhat.com जो लिखेगा, वही टिकेगा
ब्रेकिंग न्यूज़

ललितपुर। मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े छोटे शहर ललितपुर का एक साधारण परिवार से आने वाला युवक आज अपनी मेहनत और जुनून के दम पर देश का नाम रोशन करने जा रहा है। कार्तिक करोसिया, जिसने हाल ही में दिल्ली में आयोजित बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, अब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंकॉक (थाईलैंड) रवाना होगा। दिल्ली में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, जो उनके साथ-साथ पूरे ललितपुर के लिए गर्व की बात है।

जिले में भ्रष्टाचार चरम पर कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है कि जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो

● अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले के कोई ऐसा विभागन नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो रहा है जिले की कानून व्यवस्था से लेकर राजस्व विभाग तथा विकास विभाग या आपूर्ति विभाग जैसे डाक विभाग भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी अपनी झोली भरने में बेस्ट रहते हैं ग्रामीण जनता की सुनवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है जिला अधिकारी महोदय मामले को संज्ञान कभी नहीं लेती है ऐसे अधिकारियों द्वारा सरकार को बदनाम किया जा रहा है इन पर कार्रवाई न होना कर्मचारियों पर शिकंज ना कसना खुलीछूट दे रखी है कैसे जनता को न्याय मिलेगा

कलवारी उपडाकघर में ग्राहक परेशान, अपने ही पैसे के लिए महीनों से भटक रहा मजदूर

बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र स्थित उपडाकघर में ग्राहकों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहां लोगों को अपने ही खाते से पैसा निकालने के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

ग्राम बेलवाडाड़ निवासी सोनू का आरोप है कि वह अपने खाते से ?14,000 निकालने के लिए पिछले कई महीनों से उपडाकघर कलवारी के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। पीड़ित के मुताबिक, उपडाकघर में तैनात कैशियर 'मशीन खराब' होने का हवाला देकर उसे वापस कर देता है। इतना ही नहीं, उसका विड्रॉल फॉर्म तक स्वीकार नहीं किया गया।

सोनू ने बताया कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद उसे भीषण गर्मी में अपनी मजदूरी छोड़कर बार-बार पोस्ट ऑफिस आना पड़ रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

पीड़ित ने इस मामले की शिकायत प्रधान डाकघर के हेड पोस्टमास्टर से पीजी ग्रिवांस पोर्टल के माध्यम से की है और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ, तो आम जनता का सरकारी सेवाओं से भरोसा उठ सकता है। अब देखना यह होगा कि डाक विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को उसका पैसा कब तक मिल पाता है।

जिनकी हर तस्वीर में धड़कती थी जिंदगी... कैमरा से इतिहास रचने वाले रघु राय की कमी खलती रहेगी

बॉम्बे (मुंबई) के एक प्लेटफार्म पर लोकल ट्रेन खड़ी है। भीड़ उस पर चढ़ने के लिए दौड़ रही है किन्तु एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा हुआ अखबार को आमने-सामने से खोलकर पढ़ रहा है। रघु राय के इस अकेले फोटो ने साबित कर दिया कि इस तरह की स्टिल फोटो सिर्फ कैमरे का कमाल नहीं बल्कि इसके पीछे फोटोग्राफर की टेक्निक है, कौशल है और इसी कौशल को जीते थे रघु राय! उनका स्थेटिक सेंस और फिर कैमरे को अपनी मर्जी से चलाना वे जानते थे। इसीलिए वे पहले फोटोग्राफर थे जिन्हें फोटो एडिटर कहा गया. कैमरा टांग कर किसी रिपोर्टर के कहने पर वे फोटो नहीं खींचते थे बल्कि उनकी फोटो रिपोर्टर को विवश कर देती कि वह फोटो के अनुसार स्टोरी फाइल करे. रघु राय की फोटो ही खबर होती। उनके कारण ही अखबार के फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट कहे गये और पालेकर अवार्ड में उनकी श्रेणी भी उस मीडिया हाउस के पत्रकारों की तरह कैटेगराइज हुई।

अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के खाली पदों क्यों नहीं की भर्ती? दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट का सवाल

» दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों पर सवाल उठाया

» सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया

» 24 अगस्त 2023 से पद खाली, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के खाली पदों पर भर्ती न करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2023 से खाली पद अब तक क्यों नहीं भरे गए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कानून में यह शर्त है कि खाली जगहें जितनी जल्दी हो सके भरी जानी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि पदों को हमेशा के लिए खाली रखा जा सकता है।

नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हलफनामा में ये बताया जाए कि पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आयोग में खाली जगहें किस समय-सीमा के भीतर भरी जाएंगी।

याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 24 अगस्त 2023 से आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पदों पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि 24 अगस्त 2023 से आज तक आयोग में न तो किसी सदस्य और न ही चेयरमैन की नियुक्ति की गई है और यह एक काफी लंबा समय है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।

लखनऊ में हल्दी मेहंदी रस्म के दौरान दुल्हन के घर के बाहर हवाई फायरिंग, अपहरण की धमकी देकर भागे बदमाश

» हल्दी मेहंदी रस्म में दुल्हन के घर के सामने फायरिंग।

» कार सवारों ने गाली-गलौज कर अपहरण की धमकी दी।

» पुलिस ने तीन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। बीकेटी क्षेत्र के एक गांव में हल्दी मेहंदी रस्म के दौरान दुल्हन के घर के सामने पहुंचे कार सवारों ने गाली-गलौज करते हुए हवाई फायरिंग कर दी। ग्रामीण जुटे तो आरोपित कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। दुल्हन के पिता ने बीकेटी थाने में तीन लोगों के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय है। शुक्रवार को घर में हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम था। मेहमान और पड़ोसी भी घर पर थे। इसी बीच स्विफ्ट कार सवार तीन युवक घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। यह देख लोग सहम गए। पड़ोसियों ने विरोध जताया तो नशे में धुत आरोपित गाली-गलौज देते हुए धमकाने लगे। यह देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग जुट गए। आरोपितों ने खुद को घिरते देखा तो कार छोड़कर मौके से भाग गए। पीड़ितों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की है। पुलिस को एक खोखा मिला है। दुल्हन के पिता ने गांव के सुखदेव, अंकित और अनुज पर फायरिंग और बेटी के अपहरण की धमकी देने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। गाड़ी कब्जे में ली गई है। विवाह के दिन एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।

कानपुरः सपने बड़े, मजबूरी नौकरी की

● होमगार्ड परीक्षा में उमड़ा युवाओं का सैलाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। कानपुर में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं को उजागर कर दिया। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते ही अभ्यर्थियों की बातें साफ इशारा कर रही थीं कि वे भले ही होमगार्ड की परीक्षा दे रहे हों, लेकिन उनके सपने इससे कहीं बड़े हैं। कोई दरोगा बनना चाहता है, तो कोई प्रोफेसर बनने की राह पर है, लेकिन फिलहाल उनका एक ही लक्ष्य है–किसी भी तरह सरकारी नौकरी हासिल करना। प्रदेश में 41,424 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में कानपुर एक प्रमुख केंद्र रहा, जहां आसपास के जिलों से भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। इनमें ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा शामिल थे।

'कोई भी नौकरी मिल जाए, वही काफी है'

रायबरेली से आए अभ्यर्थी विजय कुमार यादव ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण अब वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'मेरा सपना पुलिस विभाग में जाना है, लेकिन फिलहाल कोई भी सरकारी नौकरी मिलना जरूरी है।' उन्होंने यह भी बताया कि इस बार का प्रश्नपत्र अपेक्षा से अधिक कठिन था। इसी तरह, शिव पांडेय जो पिछले छह साल से डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी इस परीक्षा को एक विकल्प के तौर पर लिया। उनका कहना है कि 'आज का पेपर अब तक दिए गए सभी पेपरों में सबसे कठिन लगा। प्रयागराज से आए सतीश कुमार मिश्रा ने कहा कि वे स्स्ष्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी के चलते अब कोई भी सरकारी नौकरी उनके लिए बेहतर विकल्प है। उन्होंने साफ कहा कि 'प्राइवेट नौकरी से बेहतर है कि कोई स्थायी सरकारी नौकरी मिल जाए। '

सपने बड़े, रास्ते कई

कई अभ्यर्थियों के सपने अभी भी ऊंचे हैं। अभिषेक, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ने बताया कि 'मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल होमगार्ड में चयन हो जाए तो यह मेरे करियर की एक शुरुआत होगी।' वहीं शुभम यादव, जो बीएससी कर रहे हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ने कहा कि 'इस समय सबसे जरूरी है नौकरी पाना, इसलिए हर परीक्षा दे रहा हूं। '

कठिन पेपर और कड़ी प्रतिस्पर्धा

अधिकांश अभ्यर्थियों ने पेपर को कठिन बताया, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। लाखों अभ्यर्थियों के बीच सीमित पदों के लिए संघर्ष यह दर्शाता है कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं में किस स्तर की होड़ है।

बेरोजगारी की सच्चाई आई सामने

यह परीक्षा सिर्फ भर्ती प्रक्रिया नहीं, बल्कि युवाओं की मनोस्थिति का आईना भी बनी। जहां एक ओर बड़े-बड़े सपने हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की हकीकत उन्हें किसी भी अवसर को पकड़ने के लिए मजबूर कर रही है। कुल मिलाकर, कानपुर में हुई यह परीक्षा यह बताने के लिए काफी है कि आज का युवा लक्ष्य तो ऊंचा रखता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालकर हर मौके को भुनाने की कोशिश भी कर रहा है।

लू की हवा का प्रकोप, कैसे सांस लेंगे हम

प्रकृति का बेरहमीं से दोहन।

बेरहम तथा अप्राकृतिक प्रकृति के दोहन का परिणाम अब अपने चरम परिणामों के साथ हमारे सामने खड़ा है। आने वाले महीनों में मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तीव्र गर्मी की आशंका जताई है, वह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि दशकों से जारी प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इंटरगवर्नमेंटल क्लाइमेटिक चेंज स्टडीज की नवीनतम रिपोर्टें स्पष्ट करती हैं कि वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और यदि वर्तमान उत्सर्जन दर जारी रही तो 2030 के दशक में यह 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा। वर्ल्ड मेटियोरोलिजकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि पिछले आठ वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं और दक्षिण एशिया विशेष रूप से चरम हीटवेव की चपेट में है। जब हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ, परंतु विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमने उसी मॉडल को और तीव्र रूप में अपनाया, परिणामस्वरूप मनुष्य तो स्वतंत्र हुआ पर प्रकृति आज भी बंधनों में जकड़ी रही। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी के अनुसार दुनिया हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र खो रही है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, जहाँ शहरीकरण और औद्योगीकरण की तेज रफ्तार ने जंगलों, जलस्रोतों और जैव विविधता पर गंभीर दबाव डाला है। अमूमन हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी, किंतु हमने विकास को उपभोग और विस्तार की अंधी दौड़ बना दिया, मशीनें जितनी विशाल होती गईं, मनुष्य उतना ही प्रकृति से दूर और बौना होता गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से विश्व की लगभग 33 प्रतिशत भूमि की उर्वरता प्रभावित हुई है, भारत में भी कई क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है और भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जल संकट तेजी से गहराता जा रहा है और 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध संसाधनों से दोगुनी हो सकती है। जब से हमने विकास के नाम पर उद्योगों की चिमनियाँ ऊँची कीं, मोबाइल क्रांति का बटन दबाया और डिजिटल संसार में प्रवेश किया, तब से प्रकृति की ध्वनियाँ धीमी पड़ती चली गईं, झरनों का कलकल स्वर, पक्षियों का कलरव और नदियों की जीवनदायिनी धारा जैसे विलुप्त होती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत के कई प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों समयपूर्व मृत्यु हो रही हैं। अब प्रश्न यह है कि विकास के नाम पर हमें केवल डिजिटल इंडिया चाहिए या हरित भारत की भी आवश्यकता है, क्या बच्चों के हाथ में केवल इंटरनेट देकर हम भविष्य सुरक्षित कर लेंगे या उन्हें स्वच्छ हवा, जल और हरियाली भी देनी होगी। हरा-भरा हिंदुस्तान और डिजिटल इंडिया विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, बशर्ते हम संतुलन बनाना सीखें।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ना ही जलवायु संकट से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय है और भारत ने सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की है, फिर भी यह प्रयास पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उपभोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित न करें। महात्मा गांधी का यह कथन आज और भी प्रासंगिक हो उठता है कि पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु किसी एक के लालच को नहीं। भारत की विडंबना यह है कि एक ओर महानगरों की चकाचौंध, मेट्रो, डिजिटल नेटवर्क और ऊँची इमारतें हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, किसान पसीना बहा रहा है और बच्चे दीपक या कैरोसिन की रोशनी में पढ़ रहे हैं, यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि विकास के असंतुलित मॉडल की भी देन है।

नीति आयोग की रिपोर्टों में भी जल संकट, कृषि संकट और पर्यावरणीय असंतुलन को गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि विकास का रास्ता हरित क्रांति, सतत संसाधन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण से होकर ही गुजरता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार-भाटा ऊर्जा जैसे विकल्प केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं। यदि जल, खनिज और प्राकृतिक संसाधन ही समाप्त हो गए तो न तो उद्योग चलेंगे, न ऊर्जा उत्पादन होगा और न ही डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा। किसी कवि की पंक्ति आज सच लगती है कि यदि घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, क्योंकि वही पेड़ आने वाली पीढ़ियों की सांसों का आधार बनेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की परिभाषा को पुनः परिभाषित करें, उसे केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें, तभी हम अपनी 141 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित भविष्य दे पाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जहाँ हरित क्रांति और डिजिटल प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें, न कि एक-दूसरे के विकल्प बनकर खड़े हों।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

आप में सियासी भूचाल दलबदल कानून के घेरे में 7 राज्यसभा सांसदों का भविष्य

देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी में आई इस बड़ी टूट ने न केवल पार्टी के आंतरिक हालात को उजागर किया है बल्कि दलबदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता और उसकी सीमाओं पर भी नई बहस छेड़ दी है। राज्यसभा के कई सांसदों द्वारा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा के बाद अब यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या ये सांसद अपनी सदस्यता बनाए रख पाएंगे या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं राघव चड्ढा जिनके साथ कई अन्य सांसदों ने भी पार्टी छोड़ने का दावा किया है। इनके साथ संदीप पाठक अशोक मित्तल विक्रम साहनी हरभजन सिंह स्वाति मालीवाल और नरेंद्र गुप्ता जैसे नामों का भी उल्लेख किया जा रहा है। इन सभी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा का रुख किया है। इस दावे ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है।

दूसरी ओर संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन को याचिका सौंपकर इन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन सांसदों ने संविधान की दसवीं अनुसूची का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई थी।

भारत में दलबदल विरोधी कानून जिसे दसवीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों में स्थिरता बनाए रखना और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पार्टी व्हिप से जुड़ा हुआ है। यदि कोई सांसद सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो भी उसे अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी अनुशासन बना रहे और सरकार या विपक्ष की रणनीति प्रभावित न हो।

निर्दलीय सदस्यों के लिए भी इस कानून में स्पष्ट नियम हैं। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता जिस स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनते हैं वह बाद में किसी दल का हिस्सा बनकर उनकी अपेक्षाओं के साथ समझौता न करे। हालांकि इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है जिसे विलय का प्रावधान कहा जाता है। इसके अनुसार यदि किसी दल के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य एक साथ किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दलबदल नहीं बल्कि वैध विलय माना जाता है और ऐसे सदस्यों को अयोग्यता से छूट मिल जाती है। यही वह बिंदु है जिस पर इस पूरे मामले का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा।

अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के इन सांसदों की संख्या दो तिहाई के आंकड़े तक पहुंचती है या नहीं। यदि यह संख्या पूरी होती है तो ये सांसद अपनी सदस्यता बचा सकते हैं अन्यथा इन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और राजनीतिक गणित तेजी से बदल रहा है। इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास होता है।

वर्तमान में यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के पास है जो इस मामले की सुनवाई करेंगे और तथ्यों के आधार पर फैसला देंगे। उनका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वही तय करेगा कि संबंधित सांसद संसद में बने रहेंगे या नहीं। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सभापति का निर्णय अंतिम होने के बावजूद न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दलबदल से जुड़े मामलों में सभापति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब है कि यदि किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष होता है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। यदि बड़ी संख्या में सांसद दलबदल कर बिना अयोग्यता के बच जाते हैं तो यह अन्य दलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। वहीं यदि कड़ी कार्रवाई होती है तो यह संदेश जाएगा कि दलबदल कानून अभी भी प्रभावी है और उसका उल्लंघन करने पर सख्त परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दलबदल विरोधी कानून अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा कर पा रहा है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून का उपयोग कई बार राजनीतिक हथियार के रूप में भी किया जाता है जिससे विधायकों और सांसदों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि यह कानून न हो तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है और सरकारें गिरने का खतरा बना रह सकता है।

आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जनता और संवैधानिक संस्थाओं के सामने अपनी बात रखेंगे। इस पूरे मामले पर देश की नजर बनी हुई है क्योंकि यह केवल सात सांसदों का मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि दलबदल कानून भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इसका उपयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो ताकि लोकतंत्र की मूल भावना बनी रहे। आने वाले समय में सभापति का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देगा और यह तय करेगा कि राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति पर कितना नियंत्रण संभव है।

कांतिलाल मांडोत

त्याग और समर्पण की देवी- माँ जानकी

भई प्रगट कुमारी भूमि-विदारी जनहितकारी भयहारी । अतुलित छबि भारी मुनि-मनहारी जनकदुलारी सुकुमारी ।।
सुन्दर सिंहासन तेहिं पर आसन कोटि हुताशन द्युतिकारी । सिर छत्र बिराजै सखि संग भाजै निज-निज कारज करधारी ।।
सुर सिद्ध सुजाना हनै निशाना चढ़े बिमाना समुदाई । बरसहिं बहुफूला मंगल मूला अनुकूला सिया गुन गाई ।।
दम्पति अनुरागेउ प्रेम सुपागेउ यह सुख लायउं मनलाई । अस्तुति सिय केरी प्रेमलतेरी बरनि सुचेरी सिर नाई ।। – गोस्वामी तुलसीदास

सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में जानकी नवमी या सीता नवमी का काफी महत्व है। जनक नंदिनी और भगवान राम की अर्द्धांगिनी मां सीता का प्रकटीकरण वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। यह शुभ दिवस रामनवमी के ठीक एक माह बाद पड़ता है और पूरे देश में धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ सीता मिथिला के राजा (जिसे विदेह भी कहा जाता है) राजा जनक की दत्तक पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी या जनक नंदिनी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार राजा जनक बिहार के वर्तमान सीतामढ़ी में एक यज्ञ अनुष्ठान के दौरान भूमि की जुताई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खेत के गड्ढे में एक सोने के घड़े में एक बच्ची मिली, जिसे निःसंतान राजा ने दिव्य उपहार स्वरूप अपनी प्यारी बेटी के रूप में अपना लिया। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और माँ सीता को उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भूमि के गर्भ से प्रकट होने के कारण उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है।

प्रभु श्री राम और मां सीता को एक आदर्श युगल माना जाता है। हालाँकि उनके सांसारिक मार्ग में अनेकानेक बाधाएँ आईं, लेकिन अपने संबंधों को लेकर वे सदैव अटल रहे। माँ सीता का चरित्र मानव जगत में एक आदर्श महिला का प्रतीक है और लगभग सभी परिवारों में यह आकांक्षा रहती है कि उनके यहां बेटी, जीवनसाथी, बहू, भाभी या माँ के रूप में देवी सीता जैसी कन्या हो। वे अपने समर्पण, ईमानदारी, साहस, पवित्रता और आत्म-बलिदान के लिए जानी जाती हैं। वे एक राजकुमारी थी, लेकिन वनवास गमन में पतिव्रता स्त्री की भांति उन्होने अपने पति का साथ दिया। वह लक्ष्मण और हनुमान को अपने भाई और पुत्र के रूप में प्यार करती थी। उन्होंने छद्म साधु वेशधारी रावण को भिक्षा देकर गरीबों और संतों की मदद करने की परंपरा का पालन किया। अपहरण के दौरान वानरों के बीच अपने आभूषण फेंककर उन्होने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जो बाद में श्री राम-सेना को अपहरण मार्ग का पता लगाने में सहायक सिद्ध हुआ। अपहरण के बाद, उन्होने रावण को अपने कुकर्मों के कारण उसके वंश के सर्वनाश की चेतावनी भी दी।

गर्भावस्था के दौरान सीता अपने अलगाव या अनौपचारिक तलाक से अप्रसन्न एवं कुंठित थीं, परन्तु उन्होने इस विकट परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया । उन्होने अपने बच्चों को जन्म देने और उन्हें सभी गुणों से लैस करने का निर्णय किया। अपनी मानव जीवनयात्रा के अंतिम दौर में वे एक एकल माँ के रूप में रहीं। उन्होने स्वयं को पीड़ित नहीं माना और समान अधिकारों की मांग के लिए अयोध्या वापस नहीं गई। वे राजा एवं पति के बीच भूमिका चुनने में श्री राम के आंतरिक द्वंद को समझती थी। उन्होंने राजा जनक के परिवार की प्यारी बेटी, दशरथ के परिवार की बहू, प्रभु राम की पत्नी और अंत में महाराज लव एवं कुश की माँ के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया। जब लव और कुश को अयोध्या की प्रजा और पिता राम ने स्वीकार कर लिया, तो माता के रूप में उनकी अंतिम भूमिका भी पूर्ण हो गई और वह इस क्रूर जगत, जहां पवित्रता हेतु महिलाओं से प्रमाण की आवश्यकता होती है, से मुक्ति पाने के लिए धरती माता के गर्भ में वापस लौट आई।

जानकी नवमी के शुभ दिवस पर, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सफल जीवन के लिए उपवास रखती हैं और आशीर्वाद हेतु श्री राम और मां सीता की पूजा-अर्चना करती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ-साथ धरती माता का प्रतिनिधित्व करने वाले हल की भी पूजा का विधान है। भक्तजन ऋग्वेद 4.57.6 के सीता श्लोक का जाप कर उनकी वंदना करते हैं- ''अर्वाची सुभगे भवः सीते वंदामहे त्वा । यथा नः सुभगास्सि यथाः नः सुफलास्सि ।।'' (हे मां सीते, हमें दर्शन दीजिए । हम आपके समक्ष शीश झुकाते हैं। हे रिद्धि-सिद्धि की सर्वोच्च देवी, कृपया अपनी दया और उदारता दिखाएं और हमारे लिए शुभ फलप्राप्ति के अग्रदूत बनें)। माँ सीता, उनका चरित्र और संघर्षमय जीवन भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसी मान्यता है कि जानकी नवमी पर पूजा-अनुष्ठान और व्रत करने से विनय, मातृत्व, त्याग और समर्पण जैसे गुणों की प्राप्ति होती है और एक सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। **ई० प्रभात किशोर**

आग उगलती भीषण गर्मी में प्यासे कंठों की कौन सुने दास्तां

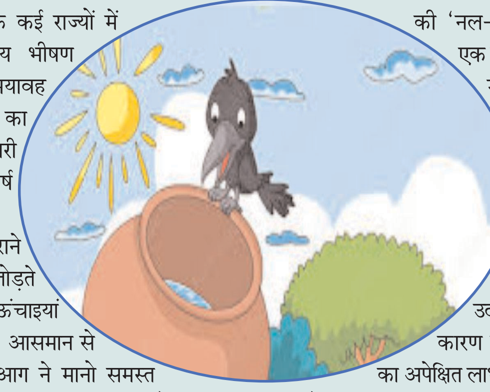

देश के कई राज्यों में इस समय भीषण और भयावह गर्मी का प्रकोप जारी है। हर वर्ष तापमान अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाइयां छू रहा है। आसमान से बरसती आग ने मानो समस्त जीव-जंतुओं के कंठ सूखा दिए हैं। यह बढ़ती हुई भीषण गर्मी कहीं न कहीं मानव द्वारा किए जा रहे पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति-विनाश का परिणाम है। इसी के चलते जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश के कारण अनेक प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे मूक वन्यजीवों के जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी प्रकृति के समस्त जीवों की मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन विडंबना यह है कि जब यही आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो जीवों के अस्तित्व पर संकट गहराना स्वाभाविक है।

यह स्वीकार करना होगा कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं कि वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते होंगे। मानव जीवन के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। विशेषकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की 'नल-जल योजना' एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक गाँवों में बनी पानी की टंकियाँ केवल दिखावा बनकर रह गई हैं। ये टंकियाँ प्यासे कंठों को राहत देने के बजाय व्यवस्था की खामियों का प्रतीक बनती जा रही हैं।

पानी हर जीव की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि इसी आवश्यकता की पूर्ति में कमी रह जाए, तो यह न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि अक्षम्य अपराध के समान है। भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर निकलने से बचते हैं, तब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मीलों दूर से पानी लाने को विवश होते हैं। जल संकट के कारण मूक पशु-पक्षियों का जीवन बचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।

प्रकृति-विनाश के चलते बढ़ती गर्मी और अस्तित्व बचाने के लिए भटकते वन्यजीव–ये दोनों ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं। ऐसे में सरकार और समाज को मिलकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक मानव और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यदि इस दिशा में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, तो देश के हर कोने में सभी जीवों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा, हर वर्ष की भाँति आग उगलती गर्मी में प्यासे मूक प्राणियों की दास्तां अधूरी ही रह जाएगी।

अरविंद रावल

कानून हैं, योजनाएं हैं, फिर भी सीवर में मौतें- आखिर जिम्मेदार कौन?

[सफाई कर्मी नहीं, यह व्यवस्था की सबसे अनदेखी लड़ाई के सिपाही हैं]

[स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चेहराः सीवर में छिपी असुरक्षित सच्चाई]

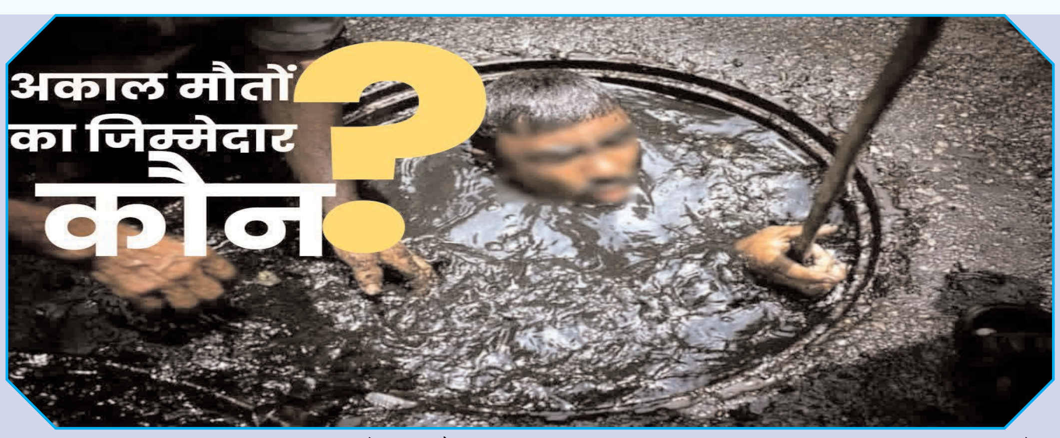

शहरों की चमक जब स्वच्छता के दावों से आत्ममुग्ध होकर दमकती है, उसी क्षण उसी चमक के भीतर छिपा अंधकार चुपचाप इंसानी जिंदगियों को निगलता चला जाता है। मार्च 2026 की शुरुआत में स्वच्छता के शिखर पर खड़े इंदौर में, चोइथराम मंडी गेट के पास एक सीवर चैंबर दो जिंदगियों का अंत बन गया–करण यादव और अजय डोडी जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से काल के गाल में समा गए।

बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वे उस घातक गहराई में उतरे; एक के अचेत होते ही दूसरा उसे बचाने भीतर गया, पर दोनों ही वापस नहीं लौट सके। यह घटना महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं, बल्कि उस विफल व्यवस्था की कठोर सच्चाई है, जो अपने सबसे कमजोर कर्मियों को सुरक्षित रखने में बार-बार असफल साबित हो रही है।

पीड़ा की यह आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कुछ ही सप्ताह बाद 15 अप्रैल 2026 को हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में वही भयावह दृश्य फिर दोहराया गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार ने तीन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतार दिया, जहां जहरीली गैसों ने दो जीवन–राजेंद्र कुमार और अब्दुल कलाम–को निगल लिया, जबकि तीसरा मजदूर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इस तरह की लगातार होती घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक खतरनाक और स्थापित होती जा रही व्यवस्था बन चुकी है। देश के अलग-अलग कोनों में फैलती यह मौतें बार-बार यह कठोर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक गरीब मजदूर अपनी जान की कीमत पर हमारी स्वच्छता की जिम्मेदारी ढोते रहेंगे।

संवैधानिक अधिकारों और मानव गरिमा की रक्षा के दावों के बीच भी इन घटनाओं की अनदेखी संभव नहीं रह सकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर मामले पर 5 मार्च 2026 और नूह मामले पर 24 अप्रैल 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में सुरक्षा उपकरणों की कमी, ठेकेदारी व्यवस्था की खामियां और मुआवजे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। यह हस्तक्षेप दिखाता है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक विफलता का परिणाम भी है।

सांख्यिकीय सच्चाइयों की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं, यह संकट और अधिक भयावह रूप लेता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 2014 से 2025 के बीच 859 सफाई कर्मियों की जान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में गई। 2017 से मार्च 2026 तक 622 मौतें दर्ज हुईं, जबकि 2026 के पहले चार महीनों में ही 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े अक्सर कम बताते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। हर साल औसतन 80 से 130 सफाई कर्मी हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटी हुई कहानियां हैं जिन्होंने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है।

कानूनों और न्यायिक आदेशों की मौजूदगी के बावजूद जमीन पर बदलाव न दिखना इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य करते हुए मृतक परिवारों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। फिर भी इंदौर और नूह मामलों में मुआवजे की घोषणा के बावजूद सवाल बना रहता है कि क्या केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त है? ठेकेदारों की लापरवाही, सुरक्षा उपकरणों की कमी और कमजोर निगरानी व्यवस्था इन कानूनों को कागजों तक सीमित कर देती है।

घोषित नीतियों और धरातल की सच्चाई के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन-2 और 'नामास्ते' जैसी योजनाओं में मैकेनाइज्ड सफाई तथा सफाई कर्मियों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इसके बावजूद इंदौर जैसे शहरों में आधुनिक मशीनें होते हुए भी उनका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, जबकि नूह जैसे क्षेत्रों में ठेकेदार जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। सस्ती मजदूरी के लालच में मानव जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है और इस पूरे तंत्र का सबसे भारी बोझ दलित समुदाय पर पड़ता है, जो आज भी सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा झेल रहा है।

इस संकट के समाधान की मांग अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस और कठोर कदम उठाए जाएं। हर शहर में 100% मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य हो, ताकि कोई मजदूर जान जोखिम में डालकर सीवर में न उतरे। ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई– भारी जुर्माना, ब्लैक लिस्टिंग और कानूनी दंड– तुरंत लागू किया जाए। प्रत्येक मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, बीमा और प्रशिक्षण अनिवार्य हों, ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो सके।

यह स्थिति हमारी सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी पर सीधा प्रश्न उठाती है कि जब हर महीने सफाई कर्मी जान गंवा रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान वास्तव में किसके लिए है। इंदौर जैसे स्वच्छता के प्रतीक शहर और नूह जैसे क्षेत्र भी इस त्रासदी से अछूते नहीं हैं, तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। यदि इन अज्ञात नायकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी, तो हमारी उपलब्धियां खोखली साबित होंगी। अब समय है कि नारों से आगे बढ़कर वास्तविक कदम उठाए जाएं, अन्यथा हर मौत हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वच्छता की कीमत किसी और की जिंदगी है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

यूपी बनेगा ग्लोबल फार्मा हब, सीएम योगी

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 फार्मा कंपनियों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' प्रदान किया, जिससे उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश होगा

ने 17 कंपनियों को दिया 'लेटर ऑफ कम्फर्ट', 2000 करोड़ का होगा निवेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 17 फॉर्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने सभी निवेशकों को सफलतम निवेश की शुभकामना दी और कहा कि आज का दिन प्रदेश के औद्योगिक व स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी व स्पीड की गारंटी है। प्रदेश अब ट्रस्ट व टाइमली डिलीवरी के लिए पहचाना जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश हर रिलायबल पॉलिसी पार्टनर के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। हम 200 देशों को सस्ती व गुणवत्तापरक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। विगत दिनों हुए फॉर्मा कॉन्क्लेव ने ग्लोबल हेल्थटेक के मैप पर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आपका निवेश केवल फॉर्मा/मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के साथ जुड़ा है। लगभग 2000 करोड़ का निवेश रिसर्च एवं डवलपमेंट में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। इस निवेश से उत्तर प्रदेश के 10 हजार से अधिक स्किल्ड/अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। यूपी में निवेश से नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। विगत 9 वर्ष में सरकार की स्पष्ट नीति व साफ नीयत के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बना है। यूपी का जीएसडीपी बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गया है। सीएम योगी ने निवेशकों से कहा कि यूपी बड़ा मार्केट है। यहां का माहौल उद्योगों के अनुकूल है। यहां पर्याप्त लैंडबैंक है। यूपी में हर सेक्टर में कार्य करने वाला वर्कफोर्स उपलब्ध है। यहां का 56 फीसदी वर्कफोर्स युवा है। इन युवाओं को स्किल, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 21 हजार से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था है। 2017 के पश्चात यूपी की सुदृढ़ कानून व्यवस्था से देश-दुनिया परिचित है। प्रदेश अब पॉलिसी पैरालिसिस से निकलकर पॉलिसी स्टेबिलिटी तक पहुंच गया है। यहां 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसी है। निवेश मित्र, निवेश सारथी, उद्यमी मित्र उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद यूपी में आए बदलावों से भी अवगत कराया। कहा कि 2017 में यूपी में 14 हजार कारखाने थे, जो आज बढ़कर 32 हजार हो गए हैं। इनसे व्यापक रोजगार सृजन हुआ है। यूपी में अब तक 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। जल्द ही 7 से 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों को यूपी की सफलता की कहानी भी बताई। 2017 तक यूपी में 40 मेडिकल कॉलेज थे, आज यह संख्या बढ़कर 83 हो गई है। हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी है। यहां दो एम्स (गोरखपुर व रायबरेली) भी हैं। राज्य में आयुष विश्वविद्यालय संचालित हो चुका है। ललितपुर में 1500 एकड़ में फॉर्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। नोएडा में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहे हैं। इसमें अब तक 100 से अधिक कंपनियां जुड़ चुकी हैं। फॉर्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर उत्सुकता जताई और विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनका निवेश ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

राहुल गांधी ने खुद बताया उन पर कितने केस दर्ज, बोले-'मैं बेल पर हूं'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गरम हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कोलकाता में आयोजित एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंच से जमकर हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार किया। राहुल गांधी का भाषण सीधा और आक्रामक था। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच अंदरखाने कोई एक समझ है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज कर रखे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर टीएमसी पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, तो फिर जांच एजेंसियां चुप क्यों हैं? रैली में बोलते हुए राहुल ने अपनी स्थिति का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वह इस समय बेल पर हैं और उनके खिलाफ कई कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई, सरकारी घर खाली करवाया गया और एजेंसियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। इसके उलट, उन्होंने पूछा कि आखिर ममता बनर्जी से ऐसी कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई। ममता बनर्जी के खिलाफ 36,38,40 केस क्यों नहीं हुए, जैसे उनपर हुए हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने टीएमसी सरकार पर लगे पुराने आरोपों को भी सामने रखा। उन्होंने शारदा और रोज वैली जैसे चिटफंड घोटालों का जिक्र किया और कहा कि लाखों लोगों की मेहनत की कमाई इन योजनाओं में फंस गई। उनका दावा था कि राज्य में 'गुंडा टैक्स' जैसी व्यवस्था चल रही है, जहां आम लोगों पर दबाव डालकर पैसा वसूला जाता है। उनके भाषण का सबसे अहम हिस्सा था यह आरोप कि भाजपा असल में टीएमसी से नहीं, बल्कि कांग्रेस से लड़ रही है। राहुल ने कहा कि भाजपा को असली चुनौती कांग्रेस और उसके नेताओं से है, इसलिए वह विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है।

संक्षिप्त खबरें

होमगार्ड परीक्षा से लौट रहे दोस्तों की बाइक डिवाइडर से टकराई, दो घायल, एक की हालत गंभीर

लालगंज (रायबरेली)। उन्नाव हाईवे पर तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बनी होमगार्ड की परीक्षा देकर लौट रहे दो दोस्तों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना कुंभडौरा गांव के पास की है। गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के गुंडा रसूलपुर गांव निवासी शैलेंद्र (28) अपने दोस्त और रिश्तेदार अनुज (18) के साथ कानपुर में होमगार्ड की परीक्षा देने गए थे। परीक्षा के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक तेज गति में थी। बाइक चला रहा अनुज हेलमेट पहने था लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों डिवाइडर पर लगे मैटेलिक गार्ड से जा टकराए। सूचना पर पहुंच पहुंची पुलिस ने जरुरी कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

स्व0 उमा शंकर जी की पंचमी पुण्यतिथि पर 28 अप्रैल को होगा भव्य धार्मिक, सामाजिक एवं भक्ति कार्यक्रम

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में उमा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रोशन सिंह 'चंदन' द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की पंचमी पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को अप्रैल को इंदिरा नगर स्थित उमा पैलेस-2 में भव्य धार्मिक, सामाजिक एवं भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुबह गौशाला में हजारों गायों को फल व चारा खिलाया जाएगा, साथ ही बंदरों एवं अन्य पशुओं को भी भोजन कराया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों द्वारा भव्य भक्ति संध्या प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। रोशन सिंह 'चंदन' ने बताया कि इस आयोजन में समाज के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार बंधु एवं क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। प्रेस कांफ्रेस के दौरान आचार्य मनोज पाण्डेय, पूर्व मैनेजर कोआपरेटिव बैंक कृपाशंकर मिश्रा , स्वामीनाथ यादव, मनीष उमारावँ, अवनीश सिंह उपस्थित रहे।

लखनऊ का पारा 43ए पार, 47.4ए डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा उत्तर प्रदेश का बांदा

लखनऊ। प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल माह में ही अधिकतम तापमान का नया रिकार्ड बना दिया है। रविवार को प्रदेश का बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म जिला रहा। राजधानी लखनऊ का दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 27 अप्रैल तक लू से राहत के आसार नहीं हैं। रविवार को प्रदेश का औसत तापमान 45°C के करीब है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लगातार दूसरे दिन भीषण गर्मी से हालात गंभीर हैं। भीषण गर्मी से उत्तर भारत उबलने की कगार पर है। प्रदेश का बांदा आज 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म जिला रहा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 43°C पहुंच गया, जो अप्रैल माह का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल को की चेतावनी जारी की थी। लखनऊ में सुबह नौ बजे से ही लू चलने लगी थी। शुक्रवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक था। 47.4°C के साथ आज बांदा देश में सबसे गर्म था।

बांदा सबसे गर्म–बांदा आज देश में सबसे गर्म रहा। यहां 47.4°C तापमान दर्ज किया गया है, अप्रैल में यह रिकॉर्ड तापमान 2022 जैसा है। इसके अलावा प्रयागराज देश में चौथे स्थान पर रहा। यहां पारा 45.5°C रहा। वाराणसी 45°C के पार के साथ पांचवें स्थान पर रहा। मेरठ और आगरा समेत कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक लू से राहत के आसार नहीं हैं। प्रदेश में कहीं-कहीं रात्रि भी भीषण गर्म रहने की संभावना है।

पदयात्रा से दिया युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का संदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। स्वदेशी जागरण मंच की लालगंज इकाई ने रविवार को स्वरोजगार जनजागरूकता पदयात्रा निकाली। यात्रा निराला नगर स्थित स्वावलंबन केंद्र से शुरू हुई। बाजार क्षेत्र से होते हुए गांधी चौराहे पर इसका समापन हुआ। पदयात्रा का नेतृत्व प्रांत संयोजक अमित सिंह वत्स ने किया। समापन पर सभी ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। अमित सिंह वत्स ने कहा कि नगर में स्वावलंबन केंद्र शुरू किया गया है। यहां योजना की जानकारी, पंजीकरण, प्रशिक्षण और ऋण संबंधी मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने सुपर 100 उद्यमी अभियान की जानकारी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 100 युवाओं का चयन कर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। पदयात्रा में स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की सूची भी वितरित की गई।

लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में आरएसएस के जिला व्यवस्था प्रमुख इंद्रेश ने अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं के पंजीकरण पर जोर दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी, चंद्र प्रकाश पांडे, रविंद्र सिंह,राजेश कुमार निर्मल मौजूद समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

होमगार्ड्स इनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा सकुशल सम्पन्न

आयोजित परीक्षा में 5132 उपस्थित एवं 1877 अनुपस्थित रहें

रायबरेली:- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया कि आज की आयोजित होमगार्ड्स इनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा में प्रथम पाली में 2547 अभ्यर्थी उपस्थित व 957 अभ्यर्थी अनुपस्थित एवं द्वितीय पाली में 2585 अभ्यर्थी उपस्थित व 920 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें, इस प्रकार दोनो पालियों में 5132 अभ्यर्थी उपस्थित व 1877 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाए की गई है, परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा भ्रमणशील रहकर लगातार निगरानी की गई।

जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं: नदी में डूबने से युवक की मौत

● परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तिलहर-शाहजहांपुर। खुशियों से भरे एक जन्मदिन समारोह का माहौल उस समय मातम में बदल गया, जब उसमें शामिल होने आया एक युवक कठिना नदी में डूब गया। जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। थाना कांट क्षेत्र के ग्राम बलीपुर निवासी शोबिंद (20) शुक्रवार को अपने दोस्त की बहन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्राम ढकिया रघा आया था। परिजनों के अनुसार, वह घर से हंसते-खेलते निकला था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी।शनिवार को वह अपने दोस्त और अन्य साथियों के साथ कठिना नदी में नहाने गया। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते लहरों में समा गया। साथियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी देर तक तलाश अभियान चलाया और आखिरकार युवक का शव नदी से बाहर निकाला जा सका। शव जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां-बाप का सहारा छिन जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता मुखिया यादव, भाई गोविंद और बहन नेहा सहित पूरे परिवार का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। उधर, मृतक के परिजनों ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शोबिंद को योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया और साजिश के तहत नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर पाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कहां कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

मलिहाबाद में उबाल: मलिहा पासी स्मृति द्वार न लगने पर उग्र प्रदर्शन

● हाईवे जाम से थमा जनजीवन, प्रशासन फिर आश्वासन पर टिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ: मलिहाबाद में मलिहा पासी स्मृति द्वार को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सड़क पर उतर आया और रविवार को क्षेत्र में बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन के बावजूद स्मृति द्वार स्थापित न होने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए लखनऊ-हरदोई हाईवे को जाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आंदोलन की खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं की भी भारी भागीदारी देखने को मिली। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन लगातार सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन

जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। करीब आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस के साथ भारी संख्या में पीएसी बल तैनात किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस आंदोलन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की मौजूदगी ने इसे और अधिक राजनीतिक महत्व दे दिया। उन्होंने मौके पर ही प्रवास पर बैठने का ऐलान करते हुए साफ कहा कि जब तक मलिहा पासी स्मृति द्वार दोबारा स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। उनके इस फैसले से आंदोलनकारियों का हौसला और बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में जुटे रहे। वहीं, सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी और लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी भी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। दोनों नेताओं ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक स्मृति द्वार का मामला नहीं, बल्कि समाज के सम्मान और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी व्यापक और उग्र रूप ले सकता है। प्रदर्शन के दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ से स्थिति नियंत्रण में रही। काफी देर तक चली बातचीत के बाद प्रशासन ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही स्मृति द्वार को पुनः स्थापित कराया जाएगा और इस बार कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अब वे केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसमें चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और बड़े स्तर पर विरोध शामिल हो सकता है। फिलहाल प्रशासन के नए आश्वासन के बाद जाम को समाप्त करा दिया गया और यातायात बहाल हो गया, वहीं मंत्री कौशल किशोर ने ऐलान किया कि जबतक यह स्मृति द्वार नहीं लग जाता तब तक वह यही पर प्रवास पर बैठे रहेंगे7लेकिन मलिहाबाद में हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन इस मुद्दे को किस तरह सुलझाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक संपन्न 14 मई से आंदोलन का निर्णय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

घाटमपुर। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर चार में संपन्न हुई, बैठक में शासनादेशो का अनुपालन न होने के विरोध में 14मई से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया,, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 18 मार्च 2025 को विधानसभा लखनऊ में बैठक थी, बैठक में प्रमुख सचिव राज्यपाल, राज्य आयुक्त दिव्यांग जन और उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव शामिल थे, बैठक में दिव्यांग जनों के 24 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी, जिसमें बधिर दिव्यांगो के दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बेरा जांच मशीन लगाने, दिव्यांग जनों को रोजगार, आवास सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने,राशन दुकानों में दिव्यांग जनों को आरक्षण कोटा देने पेंशन की राशि पांच हजार ऐ, दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का अनुपालन करानें ऊ24 सूत्रीय मांगों के मामले में निर्देश दिए गए थे,किसी भी मामले में जनपद स्तरीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस आयुक्त कार्यालय ने राज्य आयुक्त दिव्यांग जन को अनुपालन की फर्ज़ी सूचना भेज कर पत्रावली बंद कर दी, वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं होता है, और दिव्यांग जनों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है तो 14 मई से राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी,,आज इसके लिए सभी विभागों को नोटिस जारी किया गया है बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित, ओमप्रकाश, गौरव, कुमार रंजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

रास्ते में रोककर मारपीट, तीन नामजद पर केस दर्ज

तालबेहट। पूराकलां थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रहे दंपति के साथ रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, ग्राम भैसनवाराकलां निवासी अशोक यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 24 अप्रैल की रात करीब 11 बजे अपनी पत्नी संध्या के साथ ग्राम कन्धारीकलां से शादी समारोह से मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही दयालु, राहुल तथा रामपाल उर्फ हल्ले ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों व डंडों से मारपीट कर दी तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महाराज पुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने टैंट कारोबारी को कुचला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

घाटमपुर। कानपुर कमिश्नरेट अंतर्गत थाना महाराज पुर क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क पार कर रहे, टैंट कारोबारी को कुचल दिया,, गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने कांशीराम अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई,, घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया,, महाराज पुर थाना क्षेत्र के रूमा निवासी रामचंद्र 32 वर्ष टैंट कारोबारी थे,, परिवार में पिता ब्रजलाल, पत्नी रीना, और दो बच्चे,रूद्र,और त्रिशा,, परिजनों के मुताबिक रामचंद्र शनिवार को एक शादी में टैंट और डीजे लगानें का काम करने गाए गए थे,देर रात करीब 10 बजें काम ख़त्म करके घर लौटते समय हादसा हुआ,, बताया गया है प्रयागराज की ओर से आ रही एक तेज़ रफ़्तार बोलेरो ने सड़क पार कर रहे रामचंद्र को टक्कर मार दी, टक्कर के बाद भागने के प्रयास में चालक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे सिर,हाथ,और शरीर

के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटे आई,, घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों और पुलिस ने घायल को पहले एक निजी अस्पताल पहुंचाया,, महाराज पुर थाना प्रभारी निरीक्षक के अनुसार बोलेरो चालक की तलाश की जा रही है क्षेत्र में लगें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है,,, उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी चालक को वाहन समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा,, घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।

यूपी में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। देवरिया शहर के देवरिया खास स्थित मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर के पीछे विवादित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर विनियमित क्षेत्र ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की चहारदीवारी निर्माण को अनधिकृत मानते हुए उसे गिराने का आदेश दिया है। राज्य मंत्री ने निर्णय को गलत बताते हुए डीएम कोर्ट में अपील करेंगी। प्रकरण में मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास सहित अन्य स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मंदिर की भूमि व आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा कर चहारदीवारी व गेट का निर्माण कराया जा रहा है। अवर अभियंता व तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित भूमि (आराजी संख्या 2904) में दर्ज रकबे से अधिक क्षेत्र पर निर्माण किया गया है, जबकि बैनामा की गई जमीन मौके पर उपलब्ध नहीं थी। साथ ही समीप की

भूमि (आराजी 2905 व 2906) अभिलेखों में पोखरी व भीटा के रूप में दर्ज पाई गई। जांच रिपोर्ट में करीब 609.70 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना स्वीकृति निर्माण की पुष्टि हुई। न्यायालय ने माना कि यह निर्माण आरबीओ एक्ट की धारा छह का उल्लंघन है और इससे सार्वजनिक हित की भूमि प्रभावित हो रही है। विपक्षी पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज करते हुए न्यायालय ने धारा 10 के तहत ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया। साथ ही संबंधित विभाग को आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा ने ध्वस्तीकरण का आदेश भले ही पारित किया है, लेकिन 30 दिन का समय मिला है। राज्य मंत्री इस अवधि में डीएम (नियंत्रक प्राधिकारी) कोर्ट में अपील कर सकती हैं। राज्यमंत्री ने बताता की उत्तराधिकारी राजेश नारायण को मोहरा बनाकर कुछ लोग छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल चहारदीवारी कराई गई है। मामले में डीएम कोर्ट में कल तक अपील हो जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

बैंक को नकली आभूषण थमाकर लोन हासिल करने वाले जालसाजों में शामिल एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ज्ञानपुर पर आवेदक यूनियन बैंक आफ इण्डिया ज्ञानपुर जनपद भदोही में शाखा प्रबन्धक द्वारा सूचित किया गया कि शाखा में माह सितम्बर 2023 से माह मार्च 2024 के बीच मे गोल्ड लोन हुए थे जिसमे तीन गोल्ड लोन के लोन धारक जिनका नाम (1) राजेन्द्र गौतम पुत्र श्रीपत निवासी पाली जनपद भदोही (2) रवि कुमार पुत्र रामलखन निवासी पुरेटीका थाना गोपीगंज जनपद भदोही (3) नूर आलम पुत्र मो0 रफीक निवासी पुरानी बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही लोन में रखे गये स्वर्ण आभूषणों की जब बैंक द्वारा दुबारा जांच दिनांक 12.11.2024 को की गयी, सभी आभूषण नकली पाये गये जबकि इन आभूषणों को लोन होने के समय जांच बैंक द्वारा स्वकृत स्वर्णकार भावना आरनामेन्ट दुर्गा जी की गली गोपीगंज के प्रोपराइटर राजू सेठ ने किया था अतः राजू सेठ एंव लोन लेने वाले उक्त सभी ने षडयंत्र करके नकली आभूषण बैंक मे रख कर लोन धोखे से लिया और बैंक की धनराशी का दुरुपयोग किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0 अ0 सं 0- 222/ 25 धारा 319(2)/ 318(4)/316(2)/ 61(2)/316(5) बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई। अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में हो रहे अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं पंजीकृत अभियोगों से सम्बंधित वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनांक-26.04.2026 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक विश्वासघात करते हुए बैंक को नकली आभूषण 'खोटा सोना' थमाकर लोन हासिल करने की जालसाजी के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 222/ 25 धारा 319(2)/ 318(4)/ 316(2)/ 61(2)/ 316(5) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजू सेठ पुत्र स्व0 बसन्तलाल सेठ निवासी ग्राम पूरेरजई थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र करीब 41 वर्ष को सिंहपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान सम्बंधित मा0 न्यायालय किया गया।

दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान लागू, दोपहर 12 से 3 बजे तक श्रमिकों के काम पर रोक; अस्पतालों में 'कूल रूम' तैयार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते तापमान और लू की गंभीर स्थिति को देखते हुए 'हीट वेव एक्शन प्लान 2026' की विस्तृत समीक्षा कर उसे और प्रभावी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष सरकार ने अपनी रणनीति को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया है और स्कूली बच्चों, निर्माण स्थलों पर कार्य कर रहे श्रमिकों का तो विशेष ध्यान रखा ही गया है। साथ ही पक्षियों व पशुओं तक पानी की उपलब्धता पहुंचाने के लिए विभागों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। हीट वेव पीड़ितों के लिए विशेष टीमें भी तैनात की जा रही हैं।

स्कूली बच्चों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री का कहना है कि स्कूली बच्चों को गर्मी और लू से बचाने के लिए अगर जरूरत हुई तो उन्हें छुट्टी से पहले स्कूल से ओआरएस का घोल पिलाकर ही घरों के लिए रवाना किया जाएगा ताकि रास्ते में डिहाइड्रेशन का खतरा न रहे।बहुत अधिक हीट वेव की अवस्था में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों पर पानी ही नहीं, बल्कि धूप से बचाव के लिए कैप (टोपी) और गमछे के साथ जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोपहर 12:00 से 03:00 बजे के बीच बाहरी कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए विशेष निर्देश

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के थर्मल हाटस्पाट और हीट आइलैंड क्षेत्रों की संवेदनशीलता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने का गंभीर ट्रेंड देखा जा रहा है। अनुमान है कि इस सीजन में दिल्ली की बिजली पीक पावर डिमांड 9,000 मेगावाट के स्तर को पार कर जाएगी, जो पिछले वर्ष की अधिकतम मांग 8,442 मेगावाट से काफी अधिक है। इस भारी मांग को देखते हुए सीएम ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आपूर्ति में कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ रहे तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से पशु-पक्षियों के लिए पानी और छाया के निर्देश दिए हैं।

आईसीयू के लिए एक समान मानक हो: सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर, राज्य तीन हफ्तों में बनाएं एक्शन प्लान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। देशभर में आईसीयू मानकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में गहन मेडिकल यूनिट्स (आईसीयू) के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए तीन सप्ताह की समयसीमा तय की। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी विशेषज्ञों के साथ बैठक कर यथार्थवादी और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करें। पीठ ने 20 अप्रैल के आदेश में कहा कि गहन देखभाल सेवाओं के संगठन और वितरण के लिए दिशानिर्देश तैयार कर ली गई हैं, जिन पर व्यापक सहमति है। अदालत ने कहा कि ये दिशानिर्देश व्यावहारिक, लागू करने योग्य और आईसीयू के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या सचिव तत्काल विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं और इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। अदालत ने कहा कि यह योजना जमीन पर लागू होने योग्य और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि शुरुआती चरण में पांच बुनियादी जरूरतों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इनमें मानव संसाधन, प्रशिक्षित स्टाफ, उपकरण, लॉजिस्टिक्स और जरूरी ढांचे से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही इन मानकों के पालन और निगरानी के लिए स्पष्ट व्यवस्था भी बनाई जाए। पीठ ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए और पहली बैठक एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाए। संबंधित अधिकारी इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार रिपोर्ट भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग सचिव को भेजी जाएगी, जो उसे सभी राज्यों के साथ साझा करेंगे। इसके बाद एक संयुक्त बैठक कर अंतिम साझा मसौदा तैयार किया जाएगा।अगली सुनवाई 18 मई को होगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी निर्देश दिया गया है कि अदालत में पेश दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप से एडवाइजरी के रूप में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी करे व मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को तय की है।सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ को IC परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि वही मरीजों के साथ 24 घंटे रहते हैं, जबकि डॉक्टर समय-समय पर विजिट करते हैं। अदालत ने इस सुझाव को व्यावहारिक और जरूरी बताते हुए भारतीय नर्सिंग परिषद और पैरा मेडिकल परिषद को मामले में पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने इन संस्थाओं से कहा है कि वे अगली सुनवाई तक यह योजना पेश करें कि आईसीयू प्रबंधन के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में प्रशिक्षित कर्मी गंभीर मरीजों की बेहतर देखभाल कर सकें। पीठ ने निर्देश दिया कि सबसे पहले पांच ऐसे बुनियादी मुद्दों की पहचान की जाए, जो IC की न्यूनतम व्यवस्था के लिए पूर्णतः आवश्यक और अनिवार्य हों। इनमें विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन, उपकरण और आवश्यक मेडिकल ढांचे को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि गहन मेडिकल सेवाओं के संगठन और संचालन संबंधी विशेषज्ञों द्वारा तैयार दिशानिर्देश सभी राज्यों को परामर्श के रूप में भेजे जाएं और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएं।

पीठ ने कहा कि राज्यों को इन मानकों को जमीन पर लागू करने की व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करनी होगी और अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र भी बनाना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बैठकों में शामिल होने को कहा गया। राज्य स्तर की कार्यवाही पूरी होने के बाद सभी रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव को भेजी जाएंगी। इसके बाद केंद्र स्तर पर संयुक्त बैठक कर एक समान राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

श्रीभूमि जिले के पश्चिम सिंगला में बिजली गिरने से घर जलकर खाक, परिवार बाल-बाल बचा

● प्रशासन से त्वरित व स्थायी सहायता की मांग तेज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम सिंगला में गत 25 अप्रैल (शनिवार) लगभग शाम 4 बजे एक भीषण बिजली गिरने की घटना में समर दास का आवासीय घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि परिवार के सदस्य कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पड़ोसी बाप्पन दास ने सबसे पहले आग और घने धुएँ को देखा और तुरंत शोर मचाकर स्थानीय लोगों को सतर्क किया। इसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। स्थानीय लोगों की तत्परता से समर दास और उनका परिवार किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। हालांकि इस दुर्घटना में घर के भीतर रखे सभी सामान, फर्नीचर एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलने पर दरगाबंद जीपी के प्रतिनिधि दीपन सिन्हा तथा उपाध्यक्ष श्यामकुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद स्थानीय बिधायक के माध्यम से प्रशासन से संपर्क किया गया, जहां से आश्वासन दिया गया कि पीड़ित परिवार को आगामी 6 या 7 तारीख को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक राहत के रूप में प्रशासन की ओर से 10 हजार रुपये नकद एवं खाद्य सामग्री (चावल) उपलब्ध कराई गई है।इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवार के लिए त्वरित एवं स्थायी सहायता की मांग तेज कर दी है, ताकि परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः संभाल सके।

'मैं घर जाना चाहतीं हूं', व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग के बाद रो पड़ीं एरिका किर्क

● पति की पिछले साल गोली लगने से हुई थी मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिका की राजधानी में वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान शनिवार रात करीब 8:30 बजे अचानक फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एरिका किर्क को रोते हुए सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाते देखा जा सकता है। वीडियो में एरिका बेहद भावुक नजर आ रही हैं और बार-बार कहती सुनाई देती हैं, 'मैं बस घर जाना चाहती हूं।' इस घटना ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा है क्योंकि उनके पति चार्ली किर्क जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे पिछले साल सितंबर में एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी में मारे गए थे।वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में चल रहे इस कार्यक्रम के दौरान करीब पांच गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। जिसके बाद तुरंत सिक्रेट सर्विस एजेंट्स एक्टिव हो गये और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

फायरिंग के बाद एक्टिव हुई सुरक्षा एजेंसी

यह फायरिंग उस समय हुई जब वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डिनर कार्यक्रम चल रहा था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे। अचानक गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

कई बड़े नेता डिनर में थे मौजूद

कार्यक्रम में फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट सदस्य मौजूद थे। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और एफबीआई निदेशक काश पटेल को भी सुरक्षा के तहत बाहर निकाला गया।

हमलावर को किया गया गिरफ्तार

फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान कैलिफोर्निया के 31 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे की मंशा की जांच जारी है।

गाजीपुर कांड पर अखिलेश का सरकार पर हमला, बोले- 'बयान बदलवाने से सच नहीं छिपता

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर के करंडा कटरिया मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि बयान बदलवाने से सच्चाई नहीं बदली जा सकती और प्रदेश में पीड़ितों पर दबाव बनाकर सच छिपाने की कोशिश हो रही है। आरोप लगाया कि प्रदेश ने इतना कमजोर नेतृत्व कभी नहीं देखा, जो घोर अत्याचार के शिकार गरीब और बेबस लोगों पर दबाव डालकर उनके बयान बदलवाता हो। उन्होंने पूछा कि गाजीपुर में एक बेटी की हत्या होती है फिर उसमें एफआईआर दर्ज कराने में इतनी देर क्यों हुई, पीड़ित परिवार के बयान क्यों बदलवाए गए, परिवार को लगातार उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा है, पुलिस पर पथराव करने वाले वर्चस्ववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किसने रोकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवालिया निशान क्यों लग रहे हैं। इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गांव के हर घर को जमीनी हकीकत मालूम है। सभी जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और क्या कहा जा रहा है। गाजीपुर की घटना को हाथरस कांड का दोहराव बताते हुए कहा कि दोनों पीड़ित परिवार पीडीए समाज से जुड़े थे। उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को हर हाल में जारी रखेगी।

'आज सिर्फ छक्के मारेंगे', वैभव सूर्यवंशी ने SRH के गेंदबाजों को धोने का पहले ही बना लिया प्लान; सेंचुरी ठोकने के बाद खोला राज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया। हालांकि, उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। सूर्यवंशी ने मुकाबले के बाद यशस्वी जायसवाल के साथ अपनी बातचीत का खुलासा किया है। वैभव का कहना है कि जायसवाल ने उनसे सिर्फ छक्के मारने की बात कही थी। वैभव का कहना है कि जायसवाल ने उनसे आक्रामक बल्लेबाजी करने की बात कही थी। इसके बाद वे भी इसके लिए तैयार हो गए थे। बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ जायसवाल का बल्ला नहीं चला और वे 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि, सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चौकों से ज्यादा बार गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा। मैच में हार के बाद सूर्यवंशी ने जायसवाल के साथ बातचीत का खुलासा किया है।

वैभव सूर्यवंशी ने जायसवाल के साथ बातचीत का किया खुलासा

राजस्थान रॉयल्स ने अपने एक्स अकाउंट पर वैभव का एक वीडियो शेयर किया है। सूर्यवंशी ने कहा, 'जब हम टॉस जीतकर अंदर गए, तो यश भाई ने कहा कि आज चलकर सिर्फ मारते हैं। इस पर मैंने भी कहा कि हां आज चलकर सिर्फ मारते हैं। हम सिर्फ छक्के मारेंगे। यश भाई ने कहा कि चलो आज चलकर अटैक करते हैं और मैंने भी ऐसा ही करने को कहा। '

वैभव सूर्यवंशी का शतक

सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 36 गेंदों पर शतक ठोक दिया। ये आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक है। पहले स्थान पर भी सूर्यवंशी का ही नाम शामिल है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी थी।

हैदराबाद की मुकाबले में जीत

राजस्थान ने सूर्यवंशी के शतक के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। हालांकि, हैदराबाद के लिए ये काफी नहीं था। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के अर्धशतक के दम पर एसआरएच ने मुकाबले को 5 विकेट से अपना नाम कर लिया था। किशन ने 74, जबकि अभिषेक ने 57 रनों की पारी खेली थी। आईपीएल 2026 में हैदराबाद की ये लगातार चौथी जीत है।

इंदिरा गांधी से मदर टेरेसा तक, तस्वीरों से इतिहास लिखने वाले रघु राय ने दुनिया को कहा अलविदा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

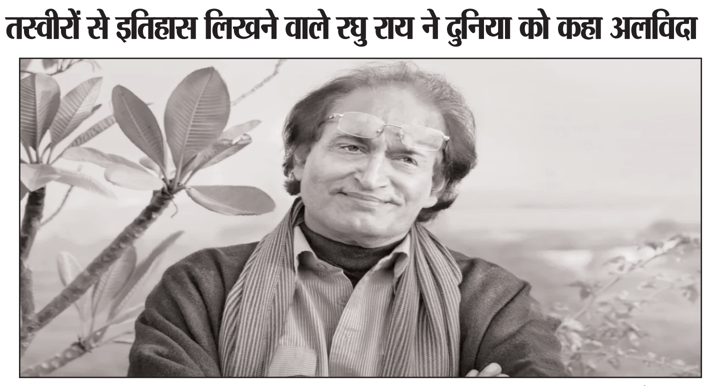

देश के दिग्गज फोटो जर्नलिस्ट और प्रतिष्ठित फोटोग्राफर रघु राय का रविवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनके परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आज शाम 4 बजे दिल्ली के लोधी श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रघु राय को भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता का 'जनक' माना जाता है। उन्होंने अपने पांच दशक से अधिक के करियर में देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं को अपने कैमरे के जरिए अमर कर दिया।

इतिहास को कैमरे में किया कैद

रघु राय का जन्म 1942 में अविभाजित भारत के झंग (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उन्होंने 1962 में फोटोग्राफी को अपना करियर बनाया।

उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ सबसे मार्मिक और अहम घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया और उनके कार्यकाल के कई ऐतिहासिक पल कैमरे में दर्ज किए। मदर टेरेसा पर की गई उनकी फोटोग्राफी को दुनिया भर में काफी सराहा गया। 1972 का बांग्लादेश शरणार्थी संकट और 1984 की भीषण भोपाल गैस त्रासदी की उनकी तस्वीरें इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था।

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस: वीकेंड पर 'धुरंधर 2' ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, स्पाई थ्रिलर ने की करोड़ों में कमाई

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर की कमाई की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। 39वें दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन दर्ज किया है। आइए जानते हैं 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 ने अपने 6वें रविवार को कितना कलेक्शन किया।

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 39

बॉक्स ऑफिस पर अपना 7वां हफ्ता शुरू करने वाली 'धुरंधर: द रिवेंज' (DhurandharÑ The Revenge) अभी भी करोड़ों रुपये छाप रही है। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 102 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। जिसके बाद से फिल्म की कमाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। रविवार की बात करें तो फिल्म ने 39वें दिन अब तक 3.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये कलेक्शन फिल्म ने 2,828 शोज और 25% ऑक्यूपेंसी के साथ दर्ज किया है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1,130.26 करोड़ रुपये हो गया है वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1,352,82 करोड़ रुपये हो गया है।

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को दिव्य शक्ति साबित करने की चुनौती दी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज- महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (ANIS) ने दो परीक्षणों के जरिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 'चमत्कारी' दावों को चुनौती दी है। पुणे मिरर की खबर के मुताबिक ANIS के संस्थापक प्रो. श्याम मानव ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को दो विशेष परीक्षणों से गुजरना होगा। अगर वे इन परीक्षणों में सफल होते हैं तो उन्हें 80 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी, लेकिन असफल होने पर इवेंट फीस के मद में जमा राशि 8 लाख जब्त कर लिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस घोषणा की काफी चर्चा है।

परीक्षण की शर्तें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यह चुनौती तीन शर्तों के साथ रखी है:

1. धीरेंद्र शास्त्री को बंद लिफाफों में रखे 10 अलग-अलग व्यक्तियों के नाम, उनके माता-पिता के नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सही-सही पहचानना होगा।
2. धीरेंद्र शास्त्री को परीक्षण वाली जगह पर बगल के में कमरे में रखी 10 अलग-अलग वस्तुओं की पहचान बिना देखे करनी होगी।
3. पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग नागपुर में होगी और दोनों पक्षों की पाँच-पाँच सदस्यीय समिति इसकी निगरानी करेगी।

प्रो. श्याम मानव ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में अंधविश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई हाल ही में अपने परिवार सहित धीरेंद्र शास्त्री से मिले, जिसे उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिहाज़ से बेहद चिंताजनक बताया। हालांकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक धीरेंद्र शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि शास्त्री ने कहना है कि 'मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, सभी शक्तियाँ बजरंगबली की हैं। मुझे केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं धर्मांतरण का विरोध करता हूँ।' इसके जवाब में एएनआईएस के प्रो श्याम मानव का कहना है कि 'अगर वे वाकई दिव्य शक्तियाँ रखते हैं, तो हमारे परीक्षण में क्या डर? हम सार्वजनिक रूप से सिद्ध करने को तैयार हैं।' धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था। वो मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। वे अपने 'दिव्य दरबार' में भूत भगाने, बिना परीक्षण के बीमारियाँ पहचानने और 'चमत्कार' करने का दावा करते हैं। बिना परीक्षण बीमारियां पहचानने और कथित चमत्कार को लेकर ही उन्हें ANIS ने अब चुनौती दी है। बागेश्वर धाम प्रमुख हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। कभी वो महिलाओं के बारे में गलत बोलने के लिए चर्चा में रहते हैं तो कभी किसी वीआईपी से मिलने पर चर्चा में आ जाते हैं। 25 अप्रैल 2026: नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री ने शनिवार को कहा कि हिन्दुओं को कम से कम चार बच्चे पैदा करना चाहिए। जिसमें वो एक बच्चा आरएसएस को सौंप दें। उनके इस बयान पर खासा विवाद हो रहा है। जनवरी 2023 मे ANIS ने नागपुर पुलिस में महाराष्ट्र के काला जादू-विरोधी कानून (2013) के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि 'दिव्य दरबार' और 'प्रेत दरबार' की आड़ में आम लोगों को ठगा जा रहा है। प्रो. मानव ने तब 30 लाख की चुनौती दी थी। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने जाँच के बाद शास्त्री को क्लीन चिट दे दी। पटना में आयोजित दरबार में शास्त्री ने 'हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे' का नारा दिया। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने कड़ा एतराज जताया। पटना में उनके पोस्टरों पर कालिख पोती गई और 'चोर' तथा '420' जैसे शब्द लिखे गए। फरवरी 2023 में शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को गढ़ा गाँव में एक दलित परिवार की शादी में हथियार लहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शालिग्राम गर्ग और उनके साथियों ने बागेश्वर धाम के एक देखभालकर्ता के घर में घुसकर महिलाओं पर डंडे और छड़ों से हमला किया, जिसमें एक नाबालिग लड़की का हाथ टूट गया। बुजुर्ग सदस्यों पर भी हमला किया गया। कैंसर के इलाज में गोमूत्र की सलाह: 2022 में एक वीडियो सामने आया जिसमें तब 25 वर्षीय शास्त्री एक युवक को उसकी कैंसर पीड़ित माँ, जो चौथे चरण में थीं, को गोमूत्र पिलाने की सलाह देते दिखे। इस वीडियो पर व्यापक आलोचना हुई। इन्हीं सब विवादों के बीच, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में 200 करोड़ के कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। 2024 में छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक कार्यक्रम में शास्त्री ने महाकुंभ में गैर-हिंदुओं की भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए 'मेरे आँगन में तुम्हारा क्या काम है' जैसे विवादास्पद शब्द कहे। इस बयान पर धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करने वालों ने कड़ा विरोध किया। अप्रैल 2025 में नागपुर के जामठा में भारत दुर्गा मंदिर की आधारशिला समारोह में शास्त्री ने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई युद्धों के बाद थककर अपना राज्य संत समर्थ रामदास को सौंपने की पेशकश की थी। इतिहासकारों और महाराष्ट्र के नागरिकों ने इस बयान को ऐतिहासिक तथ्यों से परे और आहत करने वाला बताया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने हिन्दुओं से चार बच्चे पैदा करने की अपील की थी और एक बच्चा आरएसएस को सौंपने को कहा था। इस बयान ने जनसंख्या नियंत्रण की बहस के बीच राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 2025 में एक पॉडकास्ट में YouTuber रणवीर इलाबादिया के एक विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शास्त्री ने कहा, 'सनातन और हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाने वाले को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए।' इस बयान को हिंसा के समर्थन के रूप में देखा गया। धीरेंद्र शास्त्री के सबसे ज्यादा कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्यों या उसकी समर्थक सरकारों के क्षेत्रों में होते हैं। शास्त्री के दरबार में BJP के कई वरिष्ठ नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, और पूर्व CM रमन सिंह शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता कमल नाथ भी 2023 के चुनाव से पहले आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। कई बार वो राजनीतिक दलों के टिकट तक तय करते नज़र आते हैं। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली से मथुरा तक हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में पदयात्रा भी की थी। आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती।

AAP में बगावत के बीच अरविंद केजरीवाल ने कोलकाता में ममता बनर्जी के लिए मांगे वोट, Giriraj Singh ने कसा तंज

आम आदमी पार्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस आंतरिक संकट के बावजूद, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोलकाता में ममता बनर्जी की टीएमसी का समर्थन करने और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने में व्यस्त हैं। केजरीवाल ने बंगाल पहुंचकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।

केजरीवाल का बीजेपी पर हमला

कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में उनके कामों को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'आज बीजेपी ने दिल्ली में हमारे किए गए सभी अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। हमने अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक बनाए, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की, जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की। 'उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि बंगाल लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी को करारा जवाब दे और उन्हें बुरी तरह हराए।